MODEL ANSWER

Q. The Supreme Court has directed the Union Government to consider the desirability of a legal framework for the protection and regulation of domestic workers' rights. Discuss the socio-economic challenges faced by domestic workers in India.

Domestic workers constitute a significant section of India's informal workforce, yet they remain largely unrecognized under existing labour laws. Their work, often undervalued due to social and cultural perceptions, is marked by low wages, job insecurity, and lack of social protection.

Socio-Economic Challenges Faced by Domestic Workers

1. **Lack of Legal Protection:**
   - Domestic workers are not comprehensively covered under major labour laws like the Minimum Wages Act and the Equal Remuneration Act.
   - The absence of enforceable rights leads to exploitation and inconsistent wages.
2. **Low Wages and Wage Disparities:**
   - Wages vary widely based on the nature of employment (full-time/part-time, live-in/live-out).
   - There is no uniform wage structure, leading to arbitrary payment and frequent wage cuts.
3. **Poor Working Conditions:**
   - Many domestic workers face long working hours, excessive workload, and no overtime compensation.
   - They are often expected to perform additional tasks beyond their agreed duties without extra payment.
4. **Lack of Social Security:**
   - There is no mandatory provision for health benefits, pension, or maternity benefits.
   - The informal nature of employment means that domestic workers are often excluded from schemes like Employees' State Insurance (ESI) and Provident Fund (PF).
5. **Vulnerability to Exploitation and Abuse:**
   - The private nature of their workplace (employers' homes) makes monitoring difficult, increasing risks of harassment and abuse.
   - Cases of physical, verbal, and sexual abuse often go unreported due to fear of job loss and social stigma.
6. **Absence of Employment Contracts and Registration:**
   - Lack of formal contracts leads to job insecurity and arbitrary termination of employment.
   - The demand for mandatory employer registration of workers is often resisted.
7. **Social Perceptions and Devaluation of Domestic Work:**
   - Domestic work is often seen as an extension of women's household duties rather than an economic activity.
   - The perception that domestic work requires no special skill leads to its undervaluation.

A robust legal framework is essential to safeguard the rights of domestic workers in India. Granting them formal worker status under national labour laws would ensure access to minimum wages, regulated working hours, and job security. Their inclusion in social security schemes for healthcare, maternity benefits, and pensions is crucial for long-term welfare. Establishing dedicated grievance redressal mechanisms would provide protection against exploitation and harassment. Mandatory employer registration and formal work contracts can enhance accountability and prevent arbitrary dismissals. Additionally, India should consider ratifying ILO Convention 189, which offers a

comprehensive legal framework for protecting domestic workers' rights and improving their working conditions.

The Supreme Court's directive offers a critical opportunity to recognize and regulate domestic work as a legitimate form of employment. While legislation alone may not immediately transform working conditions, it is a necessary step in redefining power relations and ensuring dignity, security, and rights for millions of domestic workers in India. A well-structured national law, incorporating regional variations and worker concerns, can create a more equitable and just framework for this essential workforce

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों के संरक्षण और विनियमन के लिए कानूनी ढांचे की वांछनीयता पर विचार करने का निर्देश दिया है। भारत में घरेलू कामगारों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए?

घरेलू कामगार भारत के अनौपचारिक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी वे मौजूदा श्रम कानूनों से काफी हद तक अपरिचित रहे हैं। उनके काम को अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं के कारण कम आंका जाता है, जो कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी से चिह्नित है।

घरेलू कामगारों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

1. **कानूनी सुरक्षा का अभाव:**
    a. घरेलू कामगारों को न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे प्रमुख श्रम कानूनों के तहत व्यापक रूप से कवर नहीं किया जाता है।
    b. उनके अधिकारों की अनुपस्थिति उनके शोषण और असंगत मज़दूरी को बढ़ावा देती है।
2. **वेतन संबंधी असमानताएँ:**
    a. वेतन रोज़गार की प्रकृति (पूर्णकालिक/अंशकालिक, लिव-इन/लिव-आउट) के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है।
    b. एक समान वेतन की संरचना के अभाव के कारणवश वेतन में मनमानी कटौती देखी जाती है।
3. **कार्य करने की खराब स्थिति:**
    a. कई घरेलू कामगारों को लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है, कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और आम तौर पर उन्हें ओवरटाइम का मुआवज़ा भी नहीं मिलता।
    b. उनसे अक्सर बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अपने तय किए गए कर्तव्यों से परे अतिरिक्त कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
4. **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:**
    a. स्वास्थ्य लाभ, पेंशन या मातृत्व लाभ के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है।
    b. रोज़गार की अनौपचारिक प्रकृति का मतलब है कि घरेलू कामगारों को अक्सर कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और भविष्य निधि (पीएफ) जैसी योजनाओं से भी बाहर रखा जाता है।
5. **शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता:**
    a. उनके कार्यस्थल (नियोक्ता के घर) की निजी प्रकृति निगरानी को मुश्किल बनाती है, जिससे उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का जोखिम बढ़ जाता है।
    b. नौकरी छूटने और सामाजिक कलंक के डर से शारीरिक, मौखिक और यौन दुर्व्यवहार के मामले अक्सर रिपोर्ट नहीं किए जाते।
6. **रोजगार अनुबंध और पंजीकरण का अभाव:**
    a. औपचारिक अनुबंधों के अभाव के कारण नौकरी की असुरक्षा सदा बनी रहती है।
    b. श्रमिकों के अनिवार्य नियोक्ता पंजीकरण की मांग का अक्सर विरोध किया जाता है।
7. **घरेलू कार्य की सामाजिक धारणाएँ और अवमूल्यन:**
    a. घरेलू कार्य को अक्सर आर्थिक गतिविधि के बजाय महिलाओं के घरेलू कर्तव्यों के विस्तार के रूप में देखा जाता है।
    b. यह धारणा कि घरेलू कार्य के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, इसके कम मूल्यांकन की ओर ले जाती है।

भारत में घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा आवश्यक है। राष्ट्रीय श्रम कानूनों के तहत उन्हें औपचारिक कर्मचारी का दर्जा देने से न्यूनतम वेतन, विनियमित कार्य की अवधि और नौकरी की सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व लाभ और पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनका समावेश दीर्घकालिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने से शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी। अनिवार्य नियोक्ता पंजीकरण और औपचारिक कार्य अनुबंध जवाबदेही बढ़ा सकते हैं और मनमाने ढंग से बर्खास्तगी को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को ILO कन्वेंशन 189 को अनुमोदित करने पर विचार करना चाहिए, जो घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

Samyak An Institute For Civil Services

सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश घरेलू कार्य को रोजगार के वैध रूप के रूप में मान्यता देने और विनियमित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हालाँकि अकेले कानून से कार्य करने की स्थितियों में तुरंत बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन यह भारत में लाखों घरेलू कामगारों के लिए शक्ति संबंधों को फिर से परिभाषित करने और सम्मान, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। एक अच्छी तरह से संरचित राष्ट्रीय कानून, जिसमें क्षेत्रीय विविधताएँ और श्रमिक चिंताएँ शामिल हैं, इस आवश्यक कार्यबल के लिए अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण ढाँचा बना सकता है।

Samyak
An Institute For Civil Services